(b) whether Government would consider instituting an inquiry into the recent press reports that Hewlett Packard is using unfair tactics to convert their joint venture in India into a wholly-owned subsidiary by pushing out from it their Indian partners and that the company has already grabbed 15 per cent equity held by some Indian promoters and taking suitable action if the allegations are found correct?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) and (b) Yes, Sir. The pattern of shareholding M/s. Hewlett Packward India is as under:—

Hewlett Packward, USA	—	40%
Blue Star	—	20%
HCL	—	15%
Public	—	25%

Proposals for enhancement of foreign equity to 100% in existing companies are considered by the Government on merits and approved subject to compliance with specified parameters. *Inter-alia*, these require a special resolution under the relevant provisions of the Companies Act for preferential allocation of equity to the foreign investors. These would also apply to the proposal of M/s. Hewlett Packward for enhancement in foreign equity levels.

देश में लघु उद्योग

2319. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में लघु उद्योग एककों की स्थापना में निरंतर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के अन्त में अलग-अलग देश के लघु औद्योगिक क्षेत्र में कितनी इकाइयां कार्यरत थीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में कुल उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा इन लघु औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में लघु औद्योगिक इकाइयों द्वारा कुल कितने प्रतिशत का उत्पादन किया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उपरोक्त वर्षों के दौरान अलग-अलग वर्ष में लघु क्षेत्र के उद्योग द्वारा देश में कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) राज्य उद्योग निदेशालय में 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (अनन्तिम) के अन्त तक पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या क्रमशः 16.48 लाख, 17.72 लाख और 19.44 लाख थी। इनमें से चालू इकाइयों की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 1987-88 के संदर्भ में पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की द्वितीय अखिल भारतीय गणना से यह पता चलता है कि कुल पंजीकृत इकाइयों में से 60% चालू हालत में पाई गई हैं। गणना के समय अन्य इकाइयां या तो बंद पाई गई थी या उनका पता नहीं लग सका।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योगों का प्रतिशत हिस्सा 1992-93 में 39.46 और 1993-94 में 40.62 था। 1994-95 के तुलनात्मक आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं।

Committee of Doctors to study Tobacco Economics

2320. SHRI MOHAN BABU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have formed a Committee of Doctors to study tobacco economics;

(b) whether it is a fact that the representatives of major tobacco growing States like Andhra Pradesh have not been included;

(c) if so, the reasons for limiting this Committee to only the medical profession; and

(d) the steps proposed to include State Governments in such committees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) to (d) The Expert Committee on Tobacco has been constituted with medical scientists economists as well as representatives of Tobacco Board, Indian Tobacco Association and Director, Central Tobacco Research Institute as its members. They will be supported in conducting the study by information supplied by the concerned departments of the Governments.

मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ

2321. **श्री शिवचरण सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सिविलसेवा (सेवा संघों की मान्यता) नियम, 1993 के लागू होने के समय कर्मचारियों के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 से 6 तक की संख्या में "मान्यता प्राप्त" कर्मचारी संघ किसी विभाग अथवा प्रतिष्ठान में अस्तित्व में थे;

(ख) यदि हां, तो 35 प्रतिशत अथवा/और 15 प्रतिशत सदस्य संख्या (सदस्यता) सिद्ध करने के उद्देश्य से कर्मचारी संघों का चयन करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित है; और

(ग) उसका क्या औचित्य है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) चूंकि सेवा संघों को मान्यता संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की जाती है, अतः उनकी संरचना तथा मंत्रालयों/विभागों में संघों की संख्या के संबंध में ब्यौरे केन्द्रीयकृत रूप से उपलब्ध नहीं है।

(ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संगमों की मान्यता) नियम, 1993 के तहत, एक विशिष्ट मंत्रालय/विभाग द्वारा परिभाषित एक भिन्न श्रेणी के लिए केवल दो सेवा संघों को मान्यता दी जा सकती है चूंकि संघ, सामान्य सेवा हितों के उन्नयन और एक सदृश समूह के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से बनाए जाते संघ, सामान्य सेवा हितों के उन्यन और एक सदृश समूह के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं।

(ग) इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार गए संघों की विशेषता प्रतिनिधित्व प्रदान करना हो और साथ ही अल्पमत को दबाया न जाए।

Shifting of firing practicing range

2322. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem captioned "Furore over Army's firing practice" as reported in Statesman dated 25th July, 1995;

(b) if so, the facts and details thereof;

(c) whether Government have any proposal to shift the existing practicing range in order to protect affected human lives and environment; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b) Yes, Sir, the newsitem was regarding Netarhat Field Firing Range, a range notified by Govt. of Bihar up to May 2002 for firing practices by the Army. A firing practice was planned on 3rd and 4th of August 1995 and civil administration was approached for clearance.This drew an adverse reaction from the civilian population and Press as reported in Statesman dated 25.7.95. To avoid any untoward incident, the scheduled firing practice was cancelled by the Army.

(c) and (d) No, Sir. However, because of continuing pressure from the local population against the use of the existing notified range, State Govt. of Bihar have indicated that they are identifying an alternative site in lieu of Netarhat Field Firing Range. No such proposal has yet been received by the Govt of India, from the State Govt.

Recommendations of Law Commission

2323. SHRI JAGMOHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the items/subjects on which the Law Commission has made